

संपादकीय

अग्निवीरों के बेहतर भविष्य की बुनियाद हो

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसकी घोषणा जून 2022 में की गई। योजना के तहत भर्ती जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। सरकार ने अब इस योजना की समीक्षा का कार्य दस अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को सौंपा है। वे इस भर्ती को अधिक आकर्षक बनाने के सुझाव भी देंगे। इसकी कमियों को दूर भी किया जा सकता है। यह भर्ती चार साल के लिए होती है, जिसमें नियमित वेतन के अतिरिक्त चार साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को लगभग बारह लाख रुपए मिलते हैं। निश्चित संख्या में तकरीबन पच्चीस फीसद अग्निवीरों को स्थायी सेवा का अवसर भी मिलता है। माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत वेतन भर्तों में बढ़ोतरी व अन्य लाभ का प्रस्ताव दिया जा सकता है। चूंकि यह योजना सरकार के प्रथम सौ दिन के एंडेंड में शामिल है इसलिए अधिकारी अपनी विस्तृत प्रस्तुति जल्दी ही प्रधानमंत्री कार्यालय को देंगे। आम चुनाव के दौरान इस योजना को विषपक्ष द्वारा लगातार निशाने पर रखा गया था। वे अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ की तरह पेश कर रहे थे। साथ ही सत्ता में आने पर इसे समाप्त करने की भी बात की जा रही थी। यह मोदी सरकार की रोजगार योजना का अभिन्न हस्सा है। हालांकि विशेषज्ञों व पूर्व सैनिकों की दलील है कि मात्र छह माह के प्रशिक्षण से सैनिक नहीं तैयार होता। दूसरे, पूर्व-अग्निवीरों को अर्ध-सैनिक बलों या पुलिस बलों जैसी सेवाओं में शामिल न किए जाने को लेकर सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसे मायावी रोजगार कहा जा रहा है। इन्हें देश के सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अयोग्य भी घोषित किए जाने को लेकर विवाद है। सेवा की इस अल्प अवधि यानी चार साल बाद ये युवा पुनर्बोर्जगारों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे में इन्हें अप्रशिक्षित कामगारों के तौर पर काम के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बाइस साल उम्र में जब ये युवा सेवा से बाहर होंगे तो नए सिरे से इन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ सकता है। लाजमी है, सरकार ने इसी तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए समीक्षा व सुझाव की कोशिश की है। उमीद की जानी चाहिए, इसमें अग्निवीरों के बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी जा सके।

भारत की विदेश नीति सदैव वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर

सजाव ठाकुर

मोदी जी ने अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फांस के राष्ट्रपति इमानुएल मेंट्रो एवं इटली की राष्ट्र प्रमुख मेलोनी तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की से अलग-अलग मुद्दों पर द्विपक्षी बैठक संपन्न की है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात संभावित है। जी-7 के सदस्य देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बैठक में पुरुजोर कोशिश की गई है। इसके अलावा पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम करने के लिए भरसक प्रयास किया गया। पर भारत और अन्य जी-7 के सदस्य देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर गंभीर मुद्दों पर नए पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। भारत हमेशा से शांति सद्व्यवहारा और सौहार्द का सर्वकालिक समर्थक रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए और इसके लिए भारत में अथक प्रयास भी हुए हैं। यह अलग बात है कि विस्तारवादी दृष्टिकोण को लेकर पुतिन और जेलेन्स्की अजीब सी राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थितियों में एक-दूसरे के सामने खड़े तथा अड़े हैं। अब इस्त्रिल-हमास युद्ध में भारत की नीति स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों और उत्तराधिकार के विरोध में रही है। भारत ने आतंकवादी संगठन हमास, हिज्बुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद का खुलकर विरोध किया है। दूसरी तरफ इस्त्रिल की बमबारी

अगर लोकस यह भारतीय

नीरज कुमार दुबे

संघायल हुए फिलास्तना नागारको के लिए संकड़ा टन खाद्य सामग्री दिवाएं और आवश्यक वस्तुएं तत्काल मुहैया कराई हैं। भारत के संबंध रूस के साथ-साथ जी-7 के सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फांस, इटली जापान, कनाडा और नारो देशों से भी मधुर हैं। इन परिस्थितियों में अरब देश भारत के प्रति युद्ध विराम की संभावनाओं की तलाश में भारतीय पहल का इंतजार कर रहा है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सभा में जॉर्डन के शांति प्रस्ताव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, 120 देशों के मतों से प्रस्ताव पारित हो गया, 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चूंकि जॉर्डन हमास को उग्रवादी संगठन नहीं मानता जबकि भारत हमास को कट्टर उग्रवादी मानने की नीति पर चल रहा है। अब भारत के लिए आगे बढ़कर पूरे विश्व का नेतृत्व करने का समय आ गया है। अब तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आहूत शांति प्रयासों तथा शांति निर्वहन संक्रियाओं का समर्थन कर रचनात्मक सहयोग हरसंभव किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर कोरिया, वियतनाम, लापोस, मिस्र, सीरिया, लाइबेरिया, युगोस्लाविया, नार्मीबिया, सोमालिया, सूडान सहित अनिगत देशों में अपनी सेनाएं वहां पर शांति बहाली के लिए अलग-अलग समय में उपलब्ध करवाई थी। भारत द्वारा विश्व शांति की स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में अनथक एवं बहुत बड़ा सहयोग किया है। उन्होंने कई देशों के मध्य पर्यवेक्षक की भूमिका भी सफलतापूर्वक निर्भाई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को शांति निरीक्षण अधिगों, समितियों तथा अंतरिम विश्वास बहाली कार्यक्रमों में बतौर सदस्य नामित भी किया है। इस भूमिका को भी भारत ने बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, वैसे भी भारत की विदेश नीति संदर्भ वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रबल पक्षधर रही है। इसीलिए भारत सरकार ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि विश्व के अनेक तनावग्रस्त संकटग्रस्त एवं युद्ध देशों के मध्य अपनी कूटनीतिक राजनैतिक भूमिका भी कर्मठता से निभाई है।

सं कोइ भी पद विपक्ष का दिया जाय। इसलिए माना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र हुंगामेदार हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि अब तक लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन आम सहमति से ही हुआ है। इसलिए विपक्ष अगले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार उतारकर यदि चुनाव की स्थिति उत्पन्न करता है तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी का चयन चूंकि हमेशा आम सहमति से होता रहा है इसलिए यदि यह परम्परा इस बार टूटी है तो यह एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी।

पीठासीन अधिकारियों का इतिहास : हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले संसद को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था और इसके अध्यक्ष पद के लिये पहली बार चुनाव 24 अगस्त 1925 में हुआ था जब स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार विठ्ठलभाई जे. पटेल ने टी. रंगचारियर के खिलाफ यह चुनाव जीता था। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर-सरकारी सदस्य विठ्ठलभाई जे. पटेल ने दो वोटों के मामूली अंतर से पहला चुनाव जीता। पटेल को 58 वोट मिले थे, जबकि टी. रंगचारियर को 56 वोट मिले थे। केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए 1925 से 1946 के बीच छह बार चुनाव हुए। विठ्ठलभाई पटेल अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद 20 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति से पुनः इस पद पर निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा के आह्वान के बाद पटेल ने 28 अप्रैल, 1930 को पद छोड़ दिया। सर मुहम्मद याकूब (78 वोट) ने नौ जुलाई, 1930 को नंद

फिर आतंकी हमले, कायम हो शांति का उजाला

ललित गग्नी

यह आशंका सच साबित हो रही है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर कश्मीर में आतंकी घटनाएँ बढ़ेंगी एवं पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर्य से फौ उठाने लगेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमले। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कटुआ और डोडा में चार दिनों में चार आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने हैं। रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस के चालक पर हुए हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। पिछ कटुआ व डोडा में हुए आतंकी हमलों में एक जवान और दो आतंकवादी मारे गए हैं। लम्बे समय की शर्ति, अमन-चैन एवं खुशहाली के बाद एक बार पिर कश्मीर में अशांति एवं आतंक के बादल मंडराये हैं। धरती के स्वर्ज की आभा पर लगे ग्रहण के बादल छंटने लगे थे कि एक बार पिर कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें तीव्र होते हुए दिख रही हैं। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है।

इन आतंकी घटनाओं को केवल सरकार ने गंभीरता से लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसमें आतंकवाद की नई चुनौती से मुकाबले की रणनीति पर विचार हुआ है। दरअसल, नई सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए इन हमलों में पाक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकिन पाकिस्तान यह बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की दृढ़ता एवं साहस को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। पिछे भी लगातार हुए आतंकी हमले चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं। ऐलओसी से लगते जम्मू के इलाके में आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना गंभीर हैं, चिन्ताजनक है। मारे गये दो आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी हथियार व सामान की बरामदगी बताती है कि पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल पिछे शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्म-कश्मीर में शांति एवं अमन



को कायम नहीं रहने देंगे ।

हमले की जिम्मेदारी पाक पोषित जैश-ए-मोहम्मद के एक गुट कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन ने ली है। बहरहाल, भारतीय सेना व सुरक्षा बल आतंकवादियों को भरपूर जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस माह के अंत तक शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का निर्वाचन आयोजन सुरक्षा बलों के लिये बड़ी चुनौती होगी। जिसको लेकर विशेष चौकसी बरतने का जरूरत है। वहीं दूसरी ओर हाल के आतंकी हमले केंद्र सरकार व राज्य प्रशासन को भावात्मक धन का मौका देते हैं।

तीन दशकों से कश्मीर घाटी दोषी औं निर्दोषी लोगों के खून की हल्दीघाटी बनी रही है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद से, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वहां शांति एवं विकास का अपूर्व वातावरण बना है। गठबंधन की केन्द्र सरकार के सामने अब बड़ा लक्ष्य है वहाँ आतंक से अमन-चैन तक लाने के लिए अब रहे मिशन को सफल करने का, लोकतंत्र का सशक्त बनाने का, विकास के कार्यक्रमों का गति देने का एवं कश्मीर के लोगों पर आई मुस्कान को कायम रखने का। बेशक यह कठिन और पेचीदा काम है लेकिन राष्ट्रीय एकता और निर्माण संवंधी कौन-सा कानून पेचीदा और कठिन नहीं रहा है? इन कठिन एवं पेचीदा कामों को आसान करना ही तो नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार का जादू रहा है। अब गठबंधन सरकार में भी वे अपने इस जादू का दिखाये। इन आतंकी हमलों ने अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है विकास कश्मीर की जनता क्यों राष्ट्र की मुख्यधारा रख जड़ नहीं पा रही है? क्या कश्मीरी लोगों में वह

व्यवस्था में अपने अधिकारों की सुरक्षा व संपत्ति के अधिकारों को लेकर मन में संशय की स्थिति में वृद्धि हुई है? हमें यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि किसी भी राज्य में आतंकवाद का उभरना स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। वहीं यह भी हकीकत है कि कश्मीरी जनमानस का दिल जीतना शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने व लोकतंत्र की बहाली से ही संभव है। अब कश्मीर में आतंक का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला होना ही चाहिए। आए दिन की हिंसक घटनाएं आम बागरियों में भय का माहौल ही बनाती हैं। माना कि रोग पुराना है, लेकिन ठोस प्रयासों के जरिए इसकी जड़ का झलाज होना ही चाहिए। कश्मीरियों में अपनी सुरक्षा के प्रति भरोसा जगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के खामों में सुरक्षा तंत्र ने काफ़ि कामयाचियां हासिल की हैं। अब जरूरत है खुफिया तंत्र को दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करने को तैयार एवं सक्षम किया जाये। घाटी में हालात सुधरने के केंद्र सरकार के दावों की सत्यता इसी से परखी जाएगी कि घाटी में अल्पसंख्यक पंडित और प्रवासी कामगार खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। वास्तव में देखा जाये तो असली लड़ाई कश्मीर में बन्दूक और सन्दूक की है, आतंकवाद और लोकतंत्र की है, अलगाववाद और एकता की है, पाकिस्तान और भारत की है। शांति का अग्रदूत बन रहा भारत एक बार पिछ युद्ध के जंग की बजाय शांति प्रयासों एवं कूटनीति से पाकिस्तान को उसकी ओकात दिखाये, यह अपेक्षित है। पाकिस्तान एक दिन भी चुप नहीं बैठा, लगातार आतंक की आंधी को पोषित करता रहा, अपनी इन कुचेष्ठाओं के चलते वह कंगाल हो चुका है, आर्थिक बदहाली में कटोरा लेकर दुनिया धूम आया, अब कोई मदद को तैयार नहीं, पिछ भी उसकी घरेलू व विदेश जीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। कश्मीर सदैव उनकी प्राथमिक सूची में रहा। पाकिस्तान जानता है कि सही क्या है पर उसकी उसमें वृत्ति नहीं है, पाकिस्तान जानता है कि गलत क्या है पर उससे उसकी निवृत्ति नहीं है। कश्मीर को अशांत करने का कोई मौका वह खोना नहीं चाहता। आज के दौर में उन्हें वाले सवालों में ज्यादातर का जवाब गठबंधन की मोदी सरकार को ही देना है, उसे सटीक जबाब देकर आतंकियों के मनसूबों को ढेर करना होगा, पड़ोसी देश की गर्दन को एक बार पिछ मरोड़ना होगा। यह बात भी सही है कि इस मसले को दलगत राजनीति से दूर रखना होगा।

अगर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो क्यों यह भारतीय राजनीति के इतिहास की बड़ी घटना होगी?

नीरज कुमार दुबे

18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों बीच चर्चाओं का दौर जारी है। दूसरी ओर पक्ष भी इस प्रयास में है कि अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा जाये। विपक्ष का ही कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह अध्यक्ष का पद उसे दे लेकिन सरकार इस दृढ़ में नहीं दिख रही है कि इन दोनों पदों में कोई भी पद विपक्ष को दिया जाये। इसलिए गवाना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र गामेदार हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक तेहास पर बजर डालें तो पता चलता है कि ब तक लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वर्चाचन आम सहमति से ही हुआ है। इसलिए पक्ष अगले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष के पद लिए उम्मीदवार उतारकर यदि चुनाव की घटिति उत्पन्न करता है तो यह स्वतंत्र भारत के तेहास में पहली बार होगा। लोकसभा में ठासीन अधिकारी का चयन चूंकि हमेशा आम सहमति से होता रहा है इसलिए यदि यह रम्परा इस बार दूरी है तो यह एक बड़ी जनीतिक घटना होगी।

जनातक धटना होगा। पीठासीन अधिकारियों का इतिहास : हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले संसद को द्वीय विधानसभा कहा जाता था और इसके ध्यक्ष पद के लिये पहली बार चुनाव 24 ग्रृष्ण 1925 में हुआ था जब स्वराजवादी पार्टी उम्मीदवार विड्लभाई जे. पटेल ने टी. गाचारियर के खिलाफ यह चुनाव जीता था। ध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर-रकारी सदस्य विड्लभाई जे. पटेल ने दो टों के मामूली अंतर से पहला चुनाव जीता। पटेल को 58 वोट मिले थे, जबकि टी. गाचारियर को 56 वोट मिले थे। केन्द्रीय धान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए 1925 1946 के बीच छह बार चुनाव हुए। विड्लभाई पटेल अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद 10 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति से पुनः इस द पर निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी द्वारा विनय अवज्ञा के आह्वान के बाद पटेल ने 28 प्रैल, 1930 को पद छोड़ दिया। सर मुहम्मद करब (78 वोट) ने नौ जुलाई, 1930 को नंद



लाल (22 वोट) के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता। याकूब तीसरी विधानसभा के आखिरी सत्र के लिए इस पद पर रहे। चौथी विधानसभा में सर इब्राहिम रहीममुल्ला (76 वोट) ने हरि सिंह और के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता, जिन्हें 36 वोट मिले। स्वास्थ्य कारणों से 7 मार्च 1933 को रहीममुल्ला ने इस्तीफ़ दे दिया और 14 मार्च 1933 को सर्वसम्मति से घण्टमुखम चेहर्वी उनके स्थान पर नियुक्त हुए। सर अब्दुर रहीम को 24 जनवरी 1935 को पांचवीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रहीम को 70 वोट मिले थे, जबकि ठी.ए.के. शेरवानी को 62 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। रहीम ने 10 साल से अधिक समय तक उच्च पद संभाला क्योंकि पांचवीं विधानसभा का कार्यकाल समय-समय पर प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनों और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ाया गया था।

केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए अंतिम मुकाबला 24 जनवरी, 1946 को हुआ था, जब कांग्रेस नेता जी.वी. मावलंकर ने कावसजी जहांगीर के खिलाफ तीन मतों के अंतर से चुनाव जीता था। मावलंकर को 66 मत मिले थे, जबकि जहांगीर को 63 मत मिले थे। इसके बाद मावलंकर को संविधान सभा

